Toppersnotes
Unleash the topper in you

CGPSC

State Civil Services

Chhattisgarh Public Service Commission

(Preliminary & Main)

भाग - 4

भारत एवं छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था

SIERRA INNOVATIONS

CGPSC

CONTENTS

भारत एवं छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था

1.	मुद्रास्फीति	1
2.	उदारीकरण	7
3.	IT की नीति	8
4.	राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद	9
5.	लोक वित्त	25
6.	भारत सरकार के खर्चे	33
7.	वित्त आयोग	37
8.	मूल्य संवर्द्धन कर	38
9.	वस्तु एवं सेवा कर	40
10.	कर टालना	43
11.	भारतीय रिजर्व बैंक	45
12.	गैर निष्पादित संपत्ति	53
13.	वित्तीय समावेश	58
14.	वित्त बाजार	61
15.	भारत के मुद्रा बाजार	62
16.	भारत के इक्विटी व्यापार	63
17.	मुद्रास्फीति और भविष्य के बाजार	71
18.	स्टार्टअप	73
19.	भारत के विदेशिक क्षेत्र	76
20.	मुद्रा कि परिवर्तनीयता	80
21.	विदेशी व्यापार नीति	81
22.	विनिमय दर	85
23.	क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी	89
24.	टोटलाइजेशन (समझौता)	89

25.	अंर्तराष्ट्रीय आर्थिक संगठन	90
26.	समावेशी विकास	100
27.	कृशि सब्सिडियों का मुद्दा	104
28.	न्यूनतम समर्थन मूल्य	110
29.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	118
30.	कृषि विपणन प्रणाली	123
31.	पशुपालन का अर्थशास्त्र	131
32.	भूमि सुधार	135
33.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	143
34.	सरकारी बजट	149
35.	काला धन/कर चोरी	153
36.	धन–शोधन	158
37.	आधारभूत संरचना	163
38.	निवेश मॉडल	170
39.	बौद्धिक संपदा अधिकार	173
40.	आर्थिक उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	178
41.	औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक नीति पर इसका प्रभाव	185
42.	गरीबी	188
43.	बेरोजगारी	194
44.	खाद्य सुरक्षा	198
45.	छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था	205

राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद
National income & Product

प्रस्तावनाः-

अर्थव्यस्था में राष्ट्रीय आय एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है । अर्थशास्त्र एवं किसी अर्थव्यवस्था की समझ के लिए राष्ट्रीय आय की गणना से जुडी अवधारणों का स्पष्ट होना आवश्यक है । वैसे तो इसका पता सामान्य तौर पर देश और वहां के लोगों की खुशहाली और उनकी प्रसन्नता से लगाते है । यह तरीका आज भी इस्तेमाल होता है हालाँकि हम यह जान चुके है कि आय से किसी भी समाज के बेहतर और कुशल होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । इस राय के पीछे कई वजहें भी हैं, जब 1990 के शुरूआती सालों में मानव विकास सूचकांक की शुरूआत हुई । इस सूचकांक में किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय को काफी प्राथमिकता दी गई थी । लेकिन समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति तभी बेहतर होती है जब इन क्षेत्रों में भी बडे पैमाने पर निवेश किया जाता हो । यही वजह है कि विकास या मानव विकास का केंद्र बिंदु आय को माना जाता है ।

अर्थात् -

- किसी देश में होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है, अर्थात् अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है ।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) :- एक वित्त में किसी देश के निवासियों द्वारा देश की आर्थिक सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जी.डी.पी. कहलाता है ।

अंतिम वस्तु एवं सेवा-

- उत्पादन प्रक्रिया से बाहर आने वाली वस्तुएँ दो प्रकार की होती हैं ।
  (1) मध्यस्थ वस्तुएँ- ऐसी वस्तुएँ जो किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में काम में ली जाती हैं, मध्यस्थ वस्तुएँ कहलाती हैं अर्थात् यह वस्तुएँ अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग में नहीं ली जाती । जैसे- कार का इंजन ।

  (2) अंतिम वस्तुएँ - ऐसी वस्तुएँ जिनका उपभोग अंतिम उपभोक्ता द्वारा किया जाता है अर्थात् इनमें उत्पादन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी होती है और उत्पादन संभव नहीं होता है । अन्तिम वस्तुएँ कहलाती हैं । जैसे - कार
- दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यस्थ वस्तुओं को छोड दिया जाता है और केवल अंतिम वस्तुओं को लिया जाता है ।
  भारत की जी.डी.पी. गणना अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन के अनुरूप बनाने के लिए इसे सकल मूल्य संवर्द्धन (GVA) आधारित बनाया गया ।

  (1) GVA_{fc} = Rent + Interest + Wages + Profit

  (2) GVA_{bp} = GVA_{fc} + उत्पादन कर - उत्पादन सब्सिडी

  (3) GDP_{mp} = GVA_{bp} + उत्पाद कर - उत्पाद सब्सिडी

- वह मूल्य जिस पर सरकार द्वारा अंतिम उपभोक्ता से कर वसूले जाते है, आधार मूल्य कहलाता है ।

वित्त वर्ष :-

- 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने की अवधि वित्त वर्ष कहलाती है ।
- वित्त वर्ष को परिवर्तित करने की संभावना ढूंढने के लिए निम्न कमेटियों का गठन किया गया ।
  (1) बेल्बी आयोग
  (2) एल.के. झा समिति
  (3) दार्निश वाचा समिति
  (4) शंकर आचार्य समिति (हाल ही में निर्मित)

उत्पादन कर - उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगने वाला कर । जैसे- कच्चे माल पर लगने वाला कर
उत्पादन सब्सिडी- उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मिलने वाली सब्सिडी उत्पादन सब्सिडी कहलाती है । जैसे- स्वदेशी कच्चे माल पर सब्सिडी
उत्पाद कर- अंतिम उत्पाद कर प्रति इकाई पर लगाया जाने वाला कर । जैसे-उत्पाद शुल्क, गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स आदि । यह कर अंतिम उपभोक्ता से वसूला जाता है जबकि उत्पादन कर उत्पादक से लिया जाता है ।
उत्पाद सब्सिडी - अंतिम उत्पाद पर उपभोक्ता को दी जाने वाली सब्सिडी जैसे - बैट्री कार पर सब्सिडी ।

जीडीपी के विभिन्न उपयोग निम्न है :-

1. जी.डी.पी. में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर (वृद्धि दर) है जैसे - किसी देश की जी.डी.पी. रू. 107 है और यह बीते साल से रू. 7 ज्यादा है तो उस देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 प्रतिशत है । जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोइंग इकॉनोमी कहते है तो मतलब यह होता है कि देश की आय परिमाणात्मक रूप से बढ रही है ।
2. यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है । इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है । लेकिन इससे देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर का पता नही चल पाता है ।
3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसके आधार पर ही किया जाता है ।

शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP) :-

- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में से मूल्य ह्रास घटाकर इसकी गणना की जाती है ।
- विभिन्न देशों में मूल्य ह्रास की गणना अलग-अलग विधियों से की जाती है । इसलिए शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार प्रत्येक देश में समान नहीं होता ।
- इस कारण शुद्ध घरेलू उत्पाद का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है ।

अन्य शब्दों में :-

शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP), किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है, जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती को घटाकर प्राप्त किया जाता है । वास्तव में जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है उपयोग के दौरान उनके मूल्य में कमी हो जाती है जिसका मतलब उस सामान का घिसने (Depreciation) या टूटने-फूटने से होता है । इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है । भारत में यह फैसला केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है । यह एक सूची जारी करता है जिसके मुताबिक विभिन्न उत्पादो में होने वाली मूल्य कटौती (घिसावट) की दूरी तय होती है ।
इस तरह से देखें तो NDP = GDP - घिसावट

ऐसे जाहिर है कि किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस साल की जीडीपी से कम होगी। अवमूल्यन को शून्य करने का कोई भी तरीका नही है। लेकिन मानव समाज इस अवमूल्यन को कम से कम करने के लिए कई तरकीबें निकाल चुका है।

मूल्य ह्रास :- उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, उत्पादन में प्रयोग में ली गई सम्पत्तियों व मशीनों में घिसावट होती है, इस कारण इनके मूल्य में आयी कमी मूल्य ह्रास कहलाती है।

शुद्ध घरेलू उत्पाद का अलग-अलग प्रयोग निम्न है :-

(1) घरेलू इस्तेमाल के लिए इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले नुकसान को समझने के लिए किया जाता है। इतना ही नही खास समयावधि के दौरान उद्योग धंधे और कारोबार में अलग-अलग क्षेत्र की स्थिति का अंदाजा भी इससे लगाया जा सकता है।

(2) अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों है ? इसकी वजह है कि दुनिया की अलग-अलग अर्थव्यवस्थाएँ अपने यहाँ मूल्य कटौती की अलग-अलग दरें निर्धारित करती हैं। यह दर मूल रूप से तार्किक आधार पर तय होती है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (**GNP**) :-

किसी अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) उस आय को कहते है जो जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोडकर हासिल होता है। इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। या,

सकल राष्ट्रीय उत्पाद **(GNP)** :- एक वित्त वर्ष के दौरान देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है।

(1) $GNP_{mp} = GDP_{mp}$ + Net factor Income from abroad (NFIFA)
(2) NFIFA = Income of Indian Citizen outside India – Income earned by foreigner in India

विदेशों से होने वाली आय में निम्नांकित पहलू शामिल हैं :-

1. निजी प्रेषण (Private Remittances)
2. विदेश कर्जे पर ब्याज (Interest of The External Loans)
3. विदेश अनुदान (External Grants)

सामान्यतः फार्मूले के मुताबिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद $ विदेशों से होने वाली आय के बराबर है, लेकिन भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आमदनी के बदले हानि होती है। लिहाजा भारत का हमेशा विदेशों से होने वाली आमदनी के बराबर होता है

सकल राष्ट्रीय उत्पाद के विभिन्न उपयोग निम्न प्रकार है –

i. इससे राष्ट्रीय आय के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है । इसके आधार पर आईएमएफ देशों को उनकी क्रय शक्ति तुल्यता (PPP) के आधार पर रैंक करता है ।
ii. राष्ट्रीय आय को आँकने के लिहाज से सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना में विस्तृत पैमाना है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिमाणात्मक के साथ-साथ गुणात्मक तस्वीरें भी पेश करता है । किसी भी अर्थव्यवस्था की आतंरिक के साथ-साथ बाहरी ताकत को भी बताता है ।
iii. यह किसी भी अर्थव्यवस्था के पैटर्न और उसके उत्पादन के व्यवहार को समझने में काफी मदद करता है । यह बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितने निर्भर है और वह उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है ।

<u>शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी (NNP)</u> :-

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है, उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) कहते है ।

या

<u>शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद **(NNP)**</u> **:-**

- इसकी गणना के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाया जाता है ।
- भारत में कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय माना जाता है ।
- बाजार मूल्य/वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय आय को शुद्ध राष्ट्रीय आय (NNI) कहा जाता है ।
- $NNP_{mp} = GNP_{mp} -$ मूल्य ह्रास (Depreciation)
- $NNP_{fc} = NNP_{mp} -$ अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी
- प्रति व्यक्ति आय = $\frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}} / \frac{NNP_{fc}}{\text{जनसंख्या}}$
- $GDP_{cp} = GDP_{mp} -$ मुद्रास्फीति (CP = स्थिर मूल्य)
- GDP_{cp} को वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है ।
- बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को नाममात्र का सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है ।

  GDP Deflator = $\frac{\text{Nomial GDP}}{\text{Real GDP}} / \frac{\text{GDPmp}}{\text{GDPcp}}$

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के विभिन्न उपयोग निम्न प्रकार है :-

i. यह किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय (National Income) (NI) है । यद्यपि जी.डी.पी. , एन.डी.पी. और जी.एन.पी. सभी राष्ट्रीय आय ही है लेकिन नेशनल इनकम (NI) के तौर पर नहीं लिखा जाता ।
ii. यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को आंकलित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है ।
iii. जब हम NNP को देश की कुल आबादी से भाग देते है । तो उससे देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है, यह प्रतिव्यक्ति सालाना आय होती है, यहाँ एक मूल बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि यह अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है । ऐसे में किसी देश में मूल्य कटौती की दर ज्यादा होने पर प्रति व्यक्ति की आय में कमी होती है ।

- भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केन्द्रीय सांख्यिकी संघठन द्वारा की जाती है ।
- राष्ट्रीय आय के लिए आकडों का संकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) और केन्द्रीय सांख्यिकी संघठन (CSO) द्वारा किया जाता है ।
- यह दोनों संस्थाएँ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के अन्तर्गत कार्य करती हैं ।

  (1) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MOSPI = Ministry of Statistics & Program Implementation)

  (2) राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन (NSSO = National Sample Survey Office/Organization)

- राष्ट्रीय आय की गणना चार मूल्यों पर आधारित होती है ।

  (1) कारक लागत

  (2) <u>बाजार मूल्य</u> – वह मूल्य जिस पर अंतिम उपभोक्ता द्वारा वस्तुएँ खरीदी जाती है बाजार मूल्य कहलाता है । इसे वर्तमान मूल्य भी कहा जाता है ।

  (3) <u>आधार मूल्य</u> –
    - राष्ट्रीय आय की तुलना के लिए किसी एक वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है ।
    - भारत में 2011-12 को आधार वर्ष घोषित किया गया है ।
    - किसी वस्तु का आधार वर्ष का मूल्य आधार मूल्य कहलाता है ।

  (4) <u>स्थिर मूल्य</u>–
    - यदि बाजार मूल्य में से मुद्रास्फीति का प्रभाव हटा दिया जाये तो वह स्थिर मूल्य कहलाता है ।
    - राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्न अवधारणाएँ प्रचलित है– सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल देशीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद

<u>मौद्रिक राष्ट्रीय आय (Nominal National Income)</u>

इसे प्रचलित या चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय (National Income at Current Price) भी कहा जाता है। इसमें आधार वर्ष की कीमतों का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में उत्पादन को लेकर वस्तुस्थिति का पता नहीं लग पाता । अतः इस राष्ट्रीय आय को अधिक महत्व नहीं दिया जाता ।

इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है–

$$GNP\ Deflator = \frac{Nominal\ GNP}{Real\ GNP}$$

GNP Deflator – सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपस्फीतिकारक
Nominal GNP – नाममात्र का सकल राष्ट्रीय उत्पाद
Real GNP – वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद

यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपस्फीतिकारक को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त करना हो तो इसके मूल्य को 100 से गुणा कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी वर्ष हेतु सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपस्फीतिकारक का मूल्य 1.25 हो तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाएगा एवं इसका मान 125 आ जाएगा। इसका अभिप्राय यह होगा कि चालू मूल्य पर जीएनपी वास्तविक जीएनपी के मूल्य का 125% होगा।

संवृद्धि एवं विकास (Growth and Development)

संवृद्धि (Growth) मात्रात्मक होती है तथा राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। विकास गुणात्मक तथा जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है।

जीवन के अच्छे गुणवत्ता में आय अथवा ग्रोथ की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन आय अथवा ग्रोथ द्वारा जीवन की गुणवत्ता को पूर्ण स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। कुछ अन्य बातों की आवश्यकता होती है जैसे – ज्ञान, अच्छा स्वास्थ्य आदि।

जीवन की गुणवत्ता (Quality of Life)

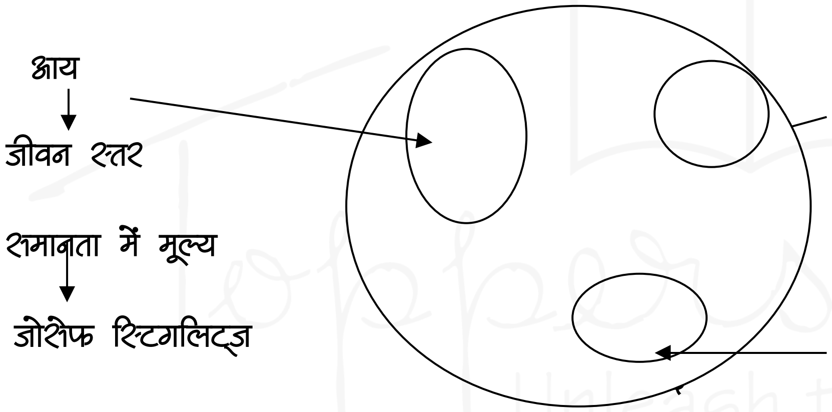

संवृद्धि तथा विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं है। यह एक-दूसरे के पूरक होते हैं, जैसे- यदि एक राष्ट्र में अच्छी संवृद्धि है तो उसमें कर संग्रह का स्तर ऊँचा होगा, जिसके द्वारा संबंधित सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य पर सामाजिक व्यय बढा सकती है।

इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एक रिसर्च के अनुसार यदि साक्षरता की दर को 20% से बढा दिया जाता है तो संबंधित राष्ट्र की संवृद्धि दर में 5% तक की बढोतरी हो सकती है।

मानव विकास सूचकांक HDI (Human Development Index)

विकास गुणात्मक होता है इसलिए उसे गणितीय रूप से नहीं मापा जा सकता है लेकिन मोटे रूप में इसकी स्थिति एवं दिशा को समझने के लिए यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया जाता है।

मानव विकास सूचकांक के निर्माण में पाकिस्तान के स्वर्गीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूब उल हक की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। हालाँकि उनके लिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन की वास्तविक गरीबी की संकल्पना प्रेरणा का स्रोत रही है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार क्षमताओं का अभाव गरीबी है। उनके अनुसार विकास स्वतंत्रता प्रदायक होता है और एक क्षमतावान व्यक्ति ही स्वतंत्र हो सकता है।

मानव विकास सूचकांक के निर्माण में निम्न आयामों तथा सूचकों का प्रयोग किया जाता है।

1- आयाम **(Dimension)** सूचक **(Indicators)**
दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीवन प्रत्याशा (Life Expeciancy) 168 वर्ष

2. ज्ञान → स्कूल के औसत वर्ष (Mean years of schooling) (5.4 वर्ष)
→ स्कूल के प्रत्याशित वर्ष (11.7 वर्ष)

3. जीवन स्तरः- वास्तविक सकल राष्ट्रीय आय (Real per capita GNI)
यू.एस.डी. (संयुक्त राज्य) (USD: United State)
Dollors: PPP
आधार : $5497

नोट :-

1. <u>सकल राष्ट्रीय आय GNI (Gross National Income)-</u>
को निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग-
GNP_{mp} = Indirect taxes + Subsidy
→ GNP_{fc}= GNI

2. यह ध्यान देने योग्य है कि 2010 से पहले UNDP द्वारा GDP_{fc} का प्रयोग किया जाता था लेकिन 2010 में यूएनडीपी द्वारा यह कहा गया कि भूमंडलीकरण के कारण कई राष्ट्रों का जीवन स्तर विदेशी साधन आय से प्रभावित हो रहा है। इसलिए विदेशी साधन आय का ध्यान रखना जरूरी है। अतः उसके द्वारा 2010 में जी. एन. आई. के प्रयोग को शुरू कर दिया गया।

3. विनिमय दर (Exchange Rate) दो प्रकार की होती है।
- चालू-विनिमय दर।
- क्रय शक्ति आधारित विनिमय दर।

चालू विनिमय दरें मुद्राओं की क्रय शक्ति में अंतर को ठीक से प्रदर्शित नहीं कर पाती। जैसे - अमेरिकन डॉलर की माँग केवल उसकी क्रय शक्ति को लेकर नहीं होती है। उसकी माँग निवेश एवं अन्य कारणों से भी होती है, जिसके चलते उसकी विनिमय दर काफी ऊँची जा सकती है। ऐसी अवस्था में क्रय शक्ति आधारित विनिमय दर का प्रयोग अधिक उपर्युक्त होता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि यू.एन.डी.पी. द्वारा शामिल किए जाने वाले सभी राष्ट्रों की सकल राष्ट्रीय आय को अमेरिकन डॉलर्स में बदला जाता है।

4. मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0–1 के बीच में होता है और जैसे-जैसे एक की दिशा में मानव विकास सूचकांक का मूल्य बदलता है तो यह माना जाता है कि मानव विकास बढ रहा है । मानव विकास सूचकांक 2015 के अनुसार 2014 के लिए भारत की मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0. 609 पाया गया । भारत का मानव विकास सूचकांक मध्यम मानव विकास को प्रदर्शित करता है ।

<u>विषमता समायोजित, **(Inequality Adjusted)**</u> -

इसे वर्ष 2010 में शुरू किया गया । यह माना गया कि विषमताएँ जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव डालती है । ऐसी अवस्था में एच डी आई में उनका समायोजन जरूरी है।

मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए मानव विकास सूचकांक में शामिल किए गए प्रत्येक मानव को लेकर संबंधित राष्ट्र में विषमताओं का पता लगाया जाता है एवं उनके आधार पर मानव विकास सूचकांक के मूल्य को नीचे लाया जाता है । उदाहरण के लिए यदि भारत को ध्यान में रखा जाए एवं विषमताओं को समायोजित किया जाए तो मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0.435 आएगा (2014 के लिए) इस प्रकार विषमताओं के कारण भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य 28.6 % नीचे चला जाता है ।

<u>लिंग विकास सूचकांक **GDI (Gender Development Index):-**</u>

यह महिलाओं के मानव विकास को पुरुषों के मानव विकास के साथ सापेक्षिक रूप से प्रस्तुत करता है इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है –

$$\frac{\text{HDI for Females}(0.525)}{\text{HDI for Males }(0.660)} = 0.795$$

<u>सुखी ग्रह सूचकांक **HPI (Happy Planet Index):-**</u>

मानव विकास सूचकांक मूल्य की एक मुख्य कमजोरी यह है कि इसमें उच्च जीवन स्तर के कारण पर्यावरणीय स्थिरता पर पडने वाले नकारात्मक प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा जाता । इस कमी को सुखी ग्रह सूचकांक द्वारा दूर किया गया है । सुखीग्रह सूचकांक का निर्माण नई आर्थिक नींव (यू.के.) द्वारा किया जाता है । इसे निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है ।

<u>नोट</u> :-

1- ''अच्छी तरह से अनुभव किया जा रहा'' के अंतर्गत लोगों द्वारा वर्तमान कृषि के स्तर को प्रदर्शित किया जाता है A इस संदर्भ में 10 में से कोई अंक देने पडते है ।

2- पारिस्थितिकीय भोजन प्रिंट, प्राकृतिक पूँजी (Natural Capital) के उपयोग को दिखाता है जो लोग अपने वर्तमान जीवन स्तर पर कर रहे होते है । इसे प्रति व्यक्ति Gha(Global Hactare) में प्रदर्शित किया जाता है । यदि पारिस्थितिकीय भोजन प्रिंट का मूल्य अधिक होता है, तो सुखी ग्रह सूचकांक का मूल्य कम होगा लेकिन पारिस्थितिकीय भोजन प्रिंट जीवन स्तर के ऊँचा होने से बढेगा इस प्रकार हम कह सकते है कि जहाँ एक ओर उच्च जीवन स्तर हाल-चाल को बढाता है वहीं दूसरी ओर समग्र भूमि के स्तर पर (संदर्भ में) खुशी के स्तर को कम करता है ।

नोट - 2

1. वर्ष 2016 की रिपोर्ट में नई आर्थिक नींव द्वारा उपरोक्त मानकों में विषमताओं को भी समायोजित किया गया है।

2- रिपोर्ट 2016 में भारत के सुखी ग्रह सूचकांक का मूल्य 29.2/100 पाया गया और भारत का इस संदर्भ में 50वां स्थान है। कोस्टारिका पहले स्थान पर है इसके द्वारा कुल ऊर्जा का 99% नवीकरणीय स्त्रोत से प्राप्त करता है। कोस्टारिका में आर्मी को हटा दिया गया तथा उस पर होने वाले खर्च को पेन्शन, स्वास्थ्य, शिक्षा की ओर मोडा गया है।

Sustainable Development

इस शब्द का प्रयोग पहली बार 1983 में ब्रुन्डलैंड कमीशन द्वारा 1983 में हमारा सामान्य भविष्य नामक रिपोर्ट में किया गया। आयोग के अनुसार– "Inter generation equity in resource use including environment is Sustainable development."

सतत विकास शब्द को लोकप्रिय बनाने में मुख्य भूमिका 1968 में रोम का क्लब की रही है। इसके द्वारा 1972 में एम.आई.टी. वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट–विकास की सीमा को जारी किया गया जिसका सांराश यह था कि दुनिया में लगातार जीडीपी में वृद्धि नहीं की जा सकती।

सतत् विकास के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों का अधिक प्रचार मिलता है–

1- शून्य वृद्धि (Zero Growth):- इसका भावार्थ यह है कि लिविंग स्टैण्डर्ड अधिक नहीं बढाया जाए तथा जीडीपी को एक स्तर पर बनाए रखा जाए।

2- अनार्थिक वृद्धि Uneconomic Growth:- ऐसी वस्तुओं के उत्पादन से प्राप्त की गई वृद्धि जिनमें संसाधनों का अधिक प्रयोग हुआ है लेकिन मानव जीवन हेतु उनकी कोई विशेष उपयोगिता नहीं है।

3- प्रतिक्षेप प्रभाव Rebound effect:- इसमें यह कहा गया कि तकनीकी का विकास होने से संसाधनों की बचत नहीं होती, बल्कि उनका अत्यधिक तेज दोहन होता है। नई तकनीकी से उत्पादकता बढती है, अधिक उत्पादकता से आय बढती है, अधिक आय से उपभोग बढता है और अधिक उपभोग के लिए अधिक उत्पादन होता है।
भारत में हरित क्रांति के लागू होने के बाद पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भूमि के अति दोहन को बढावा मिला।

ग्रीन जीडीपी-
जीडीपी - जीडीपी की उत्पत्ति के क्रम में पर्यावरण को पहुँची क्षति का अनुमान या अनुमानित मूल्य।

सकल राष्ट्रीय खुशी GNH (Gross National Happiness):-
यह अवधारणा 1972 में भूटान नरेश द्वारा दी गई।
यह अवधारणा निम्न बातों पर आधारित है–

छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था

छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था

छत्तीसगढ़ की जनसांख्यिकी

छत्तीसगढ़ भारत के मध्य भाग में एक राज्य है और 1 नवंबर, 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से अलग किया गया था। दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को इस नए राज्य में शामिल किया गया था, जो देश में इस्पात उत्पादन का 15% हिस्सा है। राज्य की सीमा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से लगती है। यह झारखंड राज्य के साथ अपनी सीमा भी साझा करता है जिसे छत्तीसगढ़ के रूप में उसी दिन बनाया गया था। राज्य में उष्णकटिबंधीय जलवायु है और छत्तीसगढ़ी राज्य में बोली जाने वाली मुख्य भाषा है। रायपुर शहर राज्य का सबसे प्रमुख शहर है और यहां एक लोकप्रिय घरेलू हवाई अड्डा है। छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 राज्य के बारे में सबसे महत्वपूर्ण आँकड़ों पर प्रकाश डालती है।

2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या लगभग 25 मिलियन है, जिससे यह भारत का 16वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बन गया है। राज्य वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया और मध्य प्रदेश से बना था। राज्य लगभग 135000 वर्ग km के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग km. 191 के आसपास है और राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। राज्य की विकास दर लगभग 22% है जो राष्ट्रीय विकास दर लगभग 17% से अधिक है। विकास और प्रगति की दिशा में तेजी से किए जा रहे प्रयासों के कारण राज्य की जनसंख्या में काफी वृद्धि हो रही है। राज्य में साक्षरता दर लगभग 73% है, जो कि सरकार के लगातार प्रयासों के कारण पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात लगभग 990 है जो एक स्वस्थ आंकड़ा है और कई अन्य राज्यों से ऊपर है। छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 के आँकड़े उन तथ्यों को प्रकट करते हैं जो राज्य के लिए एक बेहतर विकास योजना की योजना बनाने में सहायक हो सकते हैं।

राजधानी शहर जो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है, रायपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं में छत्तीसगढ़ी और हिंदी शामिल हैं। कुल छत्तीसगढ़ (CG) राज्य में 18 जिले शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा सौंपा गया ISOCODE CG है।

छत्तीसगढ़ जनसंख्या 2011

2011 की जनगणना के विवरण के अनुसार, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2.56 करोड़ है, जो 2001 की जनगणना में 2.08 करोड़ के आंकड़े से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 25,545,198 है, जिसमें पुरुष और महिला क्रमश: 12,832,895 और 12,712,303 हैं। 2001 में, कुल जनसंख्या 20,833,803 थी जिसमें पुरुष 10,474,218 थे जबकि महिलाएं 10,359,585 थीं।

शीर्ष जनसंख्या वृद्धि

1.	Kabirdham	40.71%
2.	Raipur	34.70%
3.	Bilaspur	33.29%
4.	Janjgir champa	22.94%
5.	Mahasamund	20.05%

सबसे बड़ा जिला (km²)

1.	सरगुजा	15732
2.	रायपुर	12383
3.	बस्तर	10470
4.	दुर्गा	8535
5.	बीजापुर	8530

बच्चों का प्रतिशत

1.	कबीरधाम	17.25%
2.	नारायणपुर	16.71%
3.	बीजापुर	16.65%
4.	सरगुजा	16.12%
5.	बस्तर	15.33%

उच्च घनत्व

1.	जांजगीर चंपा	420
2.	दुर्ग	392
3.	रायपुर	328
4.	बिलासपुर	322
5.	महासमुंद	216

उच्च साक्षरता

1.	दुर्ग	79.06%
2.	धमतरी	78.36%
3.	राजनंदगांव	75.96%
4.	रायपुर	75.56%
5.	रायगढ़	73.26%

उच्च लिंग अनुपात

1.	बस्तर	1023
2.	दंतेवाड़ा	1020
3.	महासमुंद	1017
4.	राजनंदगांव	1015
5.	धमतरी	1010

छत्तीसगढ़ जनसंख्या वृद्धि दर

इस दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि 22.61 प्रतिशत थी जबकि पिछले दशक में यह 18.06 प्रतिशत थी। 2011 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भारत का 2.11 प्रतिशत है। 2001 में यह आंकड़ा 2.03 प्रतिशत था।

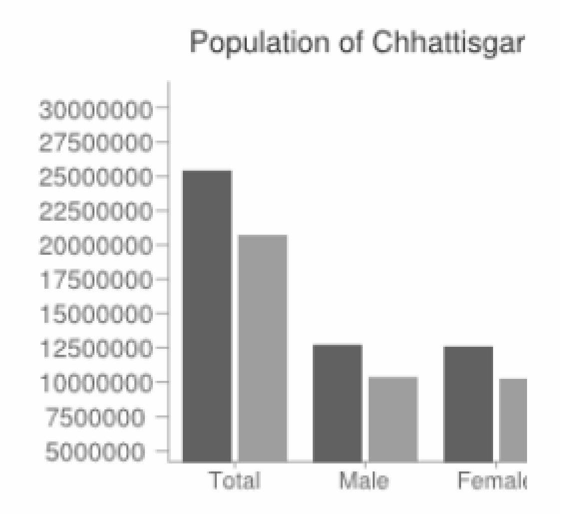

छत्तीसगढ़ साक्षरता दर 2011

छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है और 2011 की जनगणना के अनुसार 70.28 प्रतिशत है। इसमें पुरुष साक्षरता 80.27 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता 59.58 प्रतिशत है। 2001 में, छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर 64.66 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुष और महिला क्रमशः 75.70 प्रतिशत और 55.73 प्रतिशत साक्षर थे। वास्तविक संख्या में, छत्तीसगढ़ में कुल साक्षर 15,379,922 है, जिसमें पुरुष 8,807,893 और महिलाएं 6,572,029 हैं।

छत्तीसगढ़ घनत्व 2011

छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 135,192 वर्ग km है। छत्तीसगढ़ का घनत्व 189 प्रति वर्ग किमी है जो राष्ट्रीय औसत 382 प्रति वर्ग km से कम है। 2001 में छत्तीसगढ़ का घनत्व 154 प्रति वर्ग km था, जबकि 2001 में राष्ट्र औसत 324 प्रति वर्ग km था।

छत्तीसगढ़ लिंग अनुपात

छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 991 है यानी प्रत्येक 1000 पुरुष के लिए, जो 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत 940 से नीचे है। 2001 में, छत्तीसगढ़ में महिलाओं का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 था।

छत्तीसगढ़ धार्मिक डेटा

बहुत सारे दर्शक हमें छत्तीसगढ़ राज्य के धर्म का डेटा उपलब्ध कराने के लिए कह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य में हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों और ईसाइयों की वर्तमान आबादी कितनी है। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य का पूर्ण धार्मिक डेटा जारी नहीं किया है। इसके जारी होने के बाद, हम छत्तीसगढ़ जनसंख्या जनगणना 2011 के इस पृष्ठ पर विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे।

अनुमानित जनसंख्या	2.56 करोड़	2.08 करोड़
वास्तविक जनसंख्या	25,545,198	20,833,803
पुरुष	12,832,895	10,474,218
महिला	12,712,303	10,359,585
जनसंख्या वृद्धि	22.61%	18.06%
कुल जनसंख्या का प्रतिशत	2.11%	2.03%
लिंग अनुपात	991	990
बाल लिंग अनुपात	969	868

घनत्व / km²	189	154
घनत्व / mi²	489	399
क्षेत्रफल km²	135,192	135,191
क्षेत्र mi²	52,198	52,198
कुल बाल जनसंख्या (0–6 आयु)	3,661,689	3,554,916
पुरुष जनसंख्या (0–6 आयु)	1,859,935	1,800,413
महिला जनसंख्या (0–6 आयु)	1,801,754	1,754,503
साक्षरता	70.28%	64.66%
पुरुष साक्षरता	80.27%	75.70%
महिला साक्षरता	59.58%	55.73%
कुल साक्षर	15,379,922	11,173,149
पुरुष साक्षर	8,807,893	6,711,395
महिला साक्षर	6,572,029	4,461,754

छत्तीसगढ़ शहरी जनसंख्या 2011

छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में से 23.24% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का कुल आंकड़ा 5,937,237 है, जिसमें 3,035,469 पुरुष हैं और शेष 2,901,768 महिलाएं हैं। पिछले 10 वर्षों में शहरी आबादी में 23.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 956 महिलाएं थीं। बच्चों के लिए (0–6) लिंगानुपात शहरी क्षेत्र में प्रति 1000 लड़कों पर 937 लड़कियों का था। छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कुल बच्चे (0–6 आयु) 736,748 थे। शहरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में से 12.41% बच्चे (0–6) थे। छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता दर 84.05 प्रतिशत थी जिसमें पुरुष 90.58% साक्षर थे जबकि महिला साक्षरता 73.39: थी। छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्र में कुल साक्षर 4,370,966 थे।

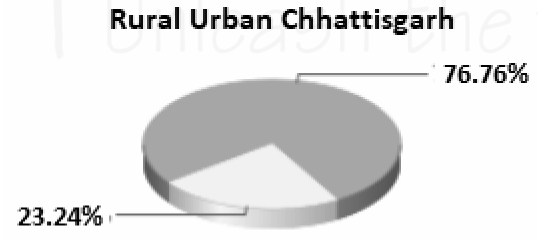

छत्तीसगढ़ ग्रामीण जनसंख्या 2011

छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या में से लगभग 76.76 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों में रहते हैं। वास्तविक संख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रमशः 9,797,426 और 9,810,535 थी। छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 19,607,961 थी। इस दशक (2001–2011) में दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि दर 76.76% थी। छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रति 1000 पुरुषों पर महिला लिंगानुपात 1001 था जबकि बच्चे के लिए (0–6 आयु) प्रति 1000 लड़कों पर 977 लड़कियां थीं। छत्तीसगढ़ में 2,924,941 बच्चे (0–6) ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। कुल ग्रामीण आबादी का 14.92 प्रतिशत बच्चों की आबादी 76.98 प्रतिशत और 55.15 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों की औसत साक्षरता दर 65.99 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल साक्षर 11,008,956 थे।

जनसंख्या(%)	76.76%	23.24%
कुल जनसंख्या	19,607,961	5,937,237
पुरुष जनसंख्या	9,797,426	3,035,469
महिला जनसंख्या	9,810,535	2,901,768
जनसंख्या वृद्धि	17.78%	41.84%
लिंग अनुपात	1001	956
बाल लिंग अनुपात (0–6)	977	937
बाल जनसंख्या (0–6)	2,924,941	736,748
बाल प्रतिशत (0–6)	14.92%	12.41%
साक्षरों	11,008,956	4,370,966
औसत साक्षरता	65.99%	84.05%
पुरुष साक्षरता	76.98%	90.58%
महिला साक्षरता	55.15%	73.39%

छत्तीसगढ़ किस तरह से महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बना रहा है

शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। युवा राज्य होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में युवाओं की शिक्षा पर विशेष बल देने की दूरदर्शिता रही है। यह आज हम राज्य के चारों ओर प्रगति की लंबी प्रगति में स्पष्ट है – चाहे वह राज्य भर में कई नए शैक्षणिक संस्थान बन रहे हों या उच्च राज्य साक्षरता दर। सरकार महिला शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर शिक्षा में लैंगिक असमानता को खत्म करने की दिशा में भी काम कर रही है। ऐसे समय में जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र से 'बेटी पढ़ाओ–बेटी बचाओ' मिशन की दिशा में काम करने का आग्रह किया है, छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य था जिसने स्नातक तक सभी लड़कियों के लिए शिक्षा मुफ्त की।

महिला शिक्षा के प्रति लोगों की सदियों पुरानी रूढ़िवादी मानसिकता के अलावा, छत्तीसगढ़ के प्रशासन को नक्सल गतिविधि के डर से भी जूझना पड़ा है, जो एक अन्य प्रमुख कारक है जो माता–पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने से रोकता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए, राज्य सरकार ने लड़कियों को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई योजनाओं और पहलों को शुरू करने को प्राथमिकता दी है।

1. सरस्वती साइकिल योजना

यह एक प्रोत्साहन योजना है जिसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2004–05 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्कूलों में लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देना और 14–18 वर्ष आयु वर्ग में स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/BPL/आदिवासी समूहों की इस आयु वर्ग की सभी लड़कियों को मुफ्त में साइकिल प्रदान की जाती है ताकि वे आसानी से अपने स्कूल से आने–जाने के लिए यात्रा कर सकें।

इस पहल ने निश्चित रूप से लाभांश का भुगतान किया है। अब लड़कियां समूहों में स्कूल से आती–जाती हैं, जो विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उनके परिवारों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करती है। इससे हाई स्कूल में लड़कियों के बीच ड्रॉपआउट दर में भारी कमी आई है।

सबसे बुरी तरह प्रभावित दस जिलों में 2007 से 2012 के बीच 4,37,799 लड़कियां इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। नामांकन संख्या 2006–07 में 5,436 से बढ़कर 2011–12 में 11,876 हो गई है। इसी अवधि के दौरान ड्रॉपआउट दर 3% से घटकर 0.9% हो गई है।

2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

2004 में शुरू की गई एक केंद्र सरकार की योजना, इसका उद्देश्य देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवासीय बालिका विद्यालय चलाना है। ये वे क्षेत्र हैं जहां राष्ट्रीय औसत (46.13%) की तुलना में कम महिला साक्षरता अनुपात और राष्ट्रीय औसत (21.59%) की तुलना में साक्षरता में उच्च लिंग अंतर है।

यह छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए विशेष रूप से सहायक है जहां 40% से अधिक आबादी SC/ST/OBC/आदिवासी है और उसे नक्सल विद्रोह की अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ता है।

3. संचार क्रांति योजना (CG-SKY)

यह देश की सबसे बड़ी मोबाइल वितरण योजना है। इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से करीब 45 लाख महिलाओं को मोबाइल मुहैया कराए जाएंगे. राज्य सरकार की ओर से कॉलेज स्तर पर छात्रों को 5 लाख फोन बांटे जाएंगे.। इससे सहभागी शासन, महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को नए बाजार आसानी से मिल जाएंगे और उन्हें वित्तीय आजादी मिलेगी। यह सूचनाओं की एक पूरी नई दुनिया भी खोलेगा जो निस्संदेह लड़कियों के बीच डिजिटल साक्षरता में सुधार करने में मदद करेगी। इन मोबाइल फोनों का वितरण अभी चल रहा है।

4. दंतेवाड़ा एजुकेशन सिटी

किसी समय में सबसे कम साक्षरता दर 42: वाला भारतीय जिला दंतेवाड़ा आज 150 एकड़ के क्षेत्र में फैले एक एजुकेशन सिटी और ₹100 करोड़ के बजट के साथ फलता–फूलता है। यह सब 2011 में शुरू हुआ जब राज्य सरकार ने शहर का उद्घाटन किया।

एजुकेशन सिटी में बालिकाओं की जरूरतों को पूरा करने वाले कई संस्थान हैं। इनमें एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आदिवासी लड़कियों के लिए एक विशेष स्कूल और ज़रूरतमंदों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने वाले कई कॉलेज शामिल हैं। एक विशेष सक्षम स्कूल में, वर्तमान में 85 विकलांग लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं जो उन्हें अपने लिए एक आशाजनक भविष्य बनाने में सक्षम बनाती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिट फर्मों में से एक झ्चडळ ने दंतेवाड़ा के एजुकेशन सिटी को दुनिया की शीर्ष 100 शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सूचीबद्ध किया है।

5. मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना

यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस योजना से 4,854 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना ने 2003–04 से 32,855 महिला स्वयं सहायता समूहों को ₹68 करोड़ से अधिक का ऋण प्रदान किया है।

6. पॉलिटेक्निक संस्थान

तकनीकी कौशल और जानकारी के निर्माण में पॉलिटेक्निक संस्थान बड़ी भूमिका निभाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि उसने पहले ही राज्य भर में चार बालिका पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित कर लिए हैं। इसके अलावा, राज्य के प्रत्येक जिले में पहले से ही कम से कम एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है। 2003–04 में, 61 सरकारी ITI 6,664 प्रशिक्षुओं को पूरा कर रहे थे, 2017–18 तक ITI की संख्या तीन गुना बढ़कर 178 हो गई है और 25,589 प्रशिक्षुओं को दिमागी रूप से प्रशिक्षित कर रहे हैं। ऐसा प्रत्येक संस्थान छात्रों को पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि उनके पास कौशल है जो उन्हें रोजगार हासिल करने में मदद कर सकता है।

7. महिला समाख्या योजना

यह एक MHRD योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना है, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए के समूहों की महिलाओं को। इसका उद्देश्य उनके आत्म–सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाना, गंभीर रूप से सोचने की क्षमता विकसित करना, विकास प्रक्रियाओं में समान भागीदारी सुनिश्चित करना और उन्हें ऐसे कौशल प्रदान करना है जो उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने की अनुमति दें।

प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र

छत्तीसगढ़ भारत के सबसे युवा और सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक है, जो व्यापार और विकास के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। व्यवसाय विकास के लिए महत्वपूर्ण कारकों द्वारा संचालित, अर्थात सुशासन, आवश्यक बुनियादी ढाँचा, बिजली के अधिशेष के साथ युग्मित, एक स्थिर श्रम वातावरण, प्रतिभा पूल, प्रचुर खनिज संसाधन और विविध वन उपज – सभी छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख व्यावसायिक गंतव्य बनाते हैं।

खनिजों और धातुओं की उपलब्धता

खनिज संपदा के मामले में छत्तीसगढ़ भारत के सबसे धनी राज्यों में शुमार है। यह 205 खानों में फैले हीरे सहित प्रमुख खनिजों की 28 किस्मों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। 2014–15 में 9.8% हिस्सेदारी के साथ छत्तीसगढ़ भारत में प्रमुख खनिज उत्पादन के मूल्य के मामले में पांचवें स्थान पर है

- भारत के टिन अयस्क भंडार के 36 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार, छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जो भारत में टिन केंद्रित करता है।
- 2014–15 में कोयला, टिन और डोलोमाइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ भारत में पहले स्थान पर था। देश के हीरे और डोलोमाइट के भंडार में राज्य का हिस्सा क्रमशः 4% और 36.5% है।

राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं :

रायपुर क्षेत्र

- खनिज, चूना पत्थर और कोयले के समृद्ध भंडार रायपुर जिले को राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनाते हैं
- नया रायपुर शहर प्रशासनिक राज्य की राजधानी है और सरकार का शहर को एक नए विश्व स्तरीय राजधानी शहर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है
- रायपुर में मोनेट इस्पात, जिंदल, सेंचुरी सीमेंट, लाफार्ज, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के साथ 158 बड़े और मध्यम स्तर के उद्योग हैं।

बिलासपुर क्षेत्र

- इस क्षेत्र में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की उपस्थिति ने क्षेत्र में सहायक औद्योगिक इकाइयों के लिए संपन्न संचालन सुनिश्चित किया है।
- 338 हेक्टेयर में फैला सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र इस क्षेत्र में स्थित है
- बिलासपुर SEC रेलवे ज़ोन का जोनल मुख्यालय भी है, जो भारत में सबसे अधिक लाभदायक रेलवे ज़ोन में से एक है, जो भारतीय रेलवे के राजस्व में लगभग 17% का योगदान देता है।

कोरबा क्षेत्र

- भारत की शक्ति राजधानी के रूप में जाना जाता है, इस क्षेत्र में कोयले और बॉक्साइट के समृद्ध भंडार हैं
- रायपुर हवाई अड्डे से 200 किमी बिलासपुर से जुड़ा हुआ है।

- इस क्षेत्र में मौजूद प्रमुख उद्योग खनन (कोयला और बॉक्साइट), बिजली उत्पादन और एल्यूमीनियम उत्पादन के क्षेत्रों में काम करते हैं।

दुर्ग–भिलाई क्षेत्र

- खनिज भंडार में समृद्ध, विशेष रूप से लौह अयस्क, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट
- सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और रायपुर हवाई अड्डे से 50 km दूर है
- इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख खिलाड़ियों में भिलाई स्टील प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) और ACC शामिल हैं
- 397 हेक्टेयर में फैला बोरई औद्योगिक विकास केंद्र एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है

बिजली की उपलब्धता

- छत्तीसगढ़ को एक बिजली अधिशेष राज्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह बिजली में आत्मनिर्भर है और पूरे राज्य में निर्बाध 24.7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले को भारत की शक्ति राजधानी के रूप में जाना जाता है।
- छत्तीसगढ़ के बड़े कोयला भंडार बिजली उत्पादन के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करते हैं।
- अगस्त 2015 तक छत्तीसगढ़ में स्थापित बिजली क्षमता 13,728.39 मेगावाट थी। स्थापित क्षमता का 33% राज्य और केंद्र सरकार का है और शेष 67% निजी कंपनियों के स्वामित्व में है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में राज्य सरकार की योजना बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 30,000 मेगावाट करने की है।
- छत्तीसगढ़ में बिजली की दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।
- बिजली सरप्लस राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ सीमेंट, एल्युमीनियम, लोहा जैसे उच्च बिजली खपत करने वाले उद्योगों के लिए एक आदर्श स्थान है।
- निर्बाध गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति के साथ, राज्य IT/ITS इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य विनिर्माण केंद्रित क्षेत्रों जैसे कई फोकस क्षेत्रों के लिए एक आकर्षक बिजली टैरिफ स्लैब प्रदान करता है।

संयोजकता

देश में केंद्रीय रूप से स्थित, छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स हब के साथ–साथ पड़ोस में विशाल उपभोक्ता बाजारों तक पहुंच के दृष्टिकोण से लाभ उठाने के लिए स्थानीय लाभ प्रदान करता है। ब्छछब्ट द्वारा नया रायपुर में 40 हेक्टेयर क्षेत्र में एक नया एकीकृत कंटेनर डिपो (ICD) विकसित किया जा रहा है। यह रायपुर में मौजूदा ICD के अतिरिक्त होगा और राज्य से प्रत्यक्ष निर्यात को और बढ़ावा देगा।

हवाई संयोजकता

- रायपुर में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा 2012–13 और 2013–14 में गैर–मेट्रो श्रेणी में भारत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्राप्तकर्ता रहा है।
- रायपुर हवाई अड्डे ने 2014–15 में 0.93 मिलियन यात्रियों को प्राप्त किया और 8,000 से अधिक उड़ानों को संभाला। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने से छत्तीसगढ़ के साथ संपर्क बढ़ेगा।
- छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साझेदारी में बिलासपुर और रायगढ़ में नागरिक हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सहमत हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ राज्य के मौजूदा हवाई संपर्क में दो अतिरिक्त हवाई अड्डे शामिल होंगे। इसके अलावा, जगदलपुर में एक नया ग्रीन फील्ड नागरिक हवाई अड्डा प्रस्तावित है।
- छत्तीसगढ़ में भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, जशपुर और सारंगढ़ क्षेत्रों में स्थित आठ हवाई पट्टी हैं।

सड़क संयोजकता

- कुल सड़क नेटवर्क का 35,241 ाउ।
- 12 राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ 2,289 ाउ का राजमार्ग नेटवर्क।
- एशियाई विकास बैंक से वार्षिकी/BOT/ऋण के आधार पर 2018 तक 2.34 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश के साथ अतिरिक्त 3,000 km सड़क नेटवर्क का निर्माण।

रेल संयोजकता

- भारत के रेल भाड़े में सबसे अधिक योगदानकर्ता– कुल राष्ट्रीय माल भाड़ा राजस्व का छठा हिस्सा है।
- राज्य में 1,187 km का मौजूदा रेल नेटवर्क है। राज्य SPV के माध्यम से अतिरिक्त 546 km रेल लाइन की योजना है।
- राज्य चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, पुणे और हैदराबाद सहित देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से निर्बाध रूप से जुड़ा हुआ है।

अतिरिक्त स्थानीय लाभ

- भारतीय उपमहाद्वीप के भूकंपीय रूप से सबसे सुरक्षित क्षेत्र में स्थित है।
- किसी भी शत्रुतापूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमा से काफी दूर।
- सात सीमावर्ती राज्यों में लगभग 500 मिलियन (भारत की आबादी का लगभग 40%) की संचयी आबादी के संभावित बाजार तक पहुंच, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 38ः का योगदान देता है।
- रायपुर से लगभग 500 km दूर विजाग बंदरगाह के माध्यम से एशियाई बाजारों (सिंगापुर, चीन, कोरिया और जापान) को निर्यात के साथ मध्य भारत के लिए एक रसद केंद्र बनने की क्षमता।

कृषि में समृद्ध

- भारत के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है, छत्तीसगढ़ कृषि में समृद्ध है, इसके 135 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 43% खेती के अधीन है।
- चावल राज्य की प्रमुख फसल है जो कुल फसल क्षेत्र का 66% है।
- दलहन, तिलहन और बागवानी शेष फसल क्षेत्र में क्रमशः 17%, 5% और 2% पर कब्जा कर लेते हैं।
- छत्तीसगढ़ मक्का, अनाज, दालों का भी प्रमुख उत्पादक है।
- छत्तीसगढ़ देश में उत्पादित कुल पपीते का 6% उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त, यह हल्दी, अदरक, अमरूद, टमाटर, बैंगन, भिंडी, मटर और गोभी जैसे बागवानी उत्पादों का एक प्रमुख योगदानकर्ता है।
- छत्तीसगढ़ में मक्का उत्पादन 2012–13 में 0.23 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2014–15 में 0.75 मिलियन मीट्रिक टन हो गया।
- 2008 और 2014 के बीच छत्तीसगढ़ में फलों और सब्जियों का उत्पादन दोगुना हो गया। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान फलों और सब्जियों की फसलों के क्षेत्र में क्रमशः 61% और 36% की दर से वृद्धि हुई।
- छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2014–15 में 0.64 मिलियन मीट्रिक टन मसालों का उत्पादन किया। राज्य में उत्पादित प्रमुख मसाले जैसे मिर्च, अदरक और हल्दी छत्तीसगढ़ में उत्पादित कुल मसालों का लगभग 78% है।
- छत्तीसगढ़ ने 2014–15 के दौरान 47,000 मीट्रिक टन फूलों का उत्पादन किया। गेंदे की किस्म में कुल फूलों की उपज का 57% हिस्सा होता है, इसके बाद हैप्पीओली और ट्यूबरोज में से प्रत्येक में 12% की दर से होता है।
- राज्य की 76 कोल्ड स्टोरेज इकाइयों में खराब होने वाली कृषि उपज के लिए 0.38 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता है।

- 2014–15 में मछली बीज उत्पादन और अंतर्देशीय मछली उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में छठे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ सालाना 1.1 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन करता है। राज्य में दूध की खपत 2020 तक 3.7 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है।
- बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती प्रति व्यक्ति आय, रोजगार की उच्च दर और राज्य में लोगों की तेजी से बदलती भोजन की आदतें और जीवन शैली राज्य में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास को गति दे रही है।

व्यापार करने की कम लागत

पूंजी लागत

- भूमि की कम लागत
- स्टील और सीमेंट के प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के कारण निर्माण की कम लागत
- कच्चे माल की कम लागत (धातु)
- वित्तीय प्रोत्साहन
- पूंजी सब्सिडी
- ब्याज सब्सिडी
- भूमि प्रीमियम पर छूट

संचालन लागत

- कम लागत श्रम
- बिजली की कम लागत
- जीवन यापन की कम लागत
- कम किराया
- उत्पादन की कम लागत
- वित्तीय प्रोत्साहन
- बिजली शुल्क में छूट
- छत्तीसगढ़ में बिजली की दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है;
- स्थानीय विनिर्माण के कारण राज्य में धातुओं और सीमेंट की लागत कम है;
- कम जनसंख्या घनत्व के कारण राज्य में भूमि की लागत देश के अन्य भागों की तुलना में कम है
- लागत प्रभावी परिवहन और रसद
- छत्तीसगढ़ में निर्माण की लागत है प्रतिस्पर्धा

छत्तीसगढ़ बजट विश्लेषण 2021–22

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 1 मार्च, 2021 को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राज्य के लिए बजट पेश किया। ध्यान दें कि COVID–19 के प्रभाव के कारण, 2020–21 सम्मान के साथ एक मानक वर्ष नहीं था। अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त के प्रदर्शन के लिए। इस नोट में, 2021–22 के बजट अनुमानों की तुलना 2019–20 के वास्तविक (चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर या CAGR के संदर्भ में) से की गई है। 2020–21 के संशोधित अनुमानों और 2021–22 के बजट अनुमानों की तुलना अनुलग्नक में प्रदान की गई है।

Toppersnotes Unleash the topper in you